POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2013/अंक 04 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अप्रेल, 2013 मूल्य 50 पैसे

उपभोक्ता जागरूकता के लिए व्यापक अभियान की जरूरत - डॉ मेहरा

जब तक व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, बनाए गए कानून और व्यवस्थाएं कोई मायना नहीं रखती। सवाल करने से जागरूकता आती है, इसलिए उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए हमें प्रश्नकर्ता समाज के गठन के लिए व्यापक अभियान चलाना होगा। साथ ही उपभोक्ता अपने दायित्वों का भी जिम्मेदारी से पालन करे।

उक्त विचार डॉ. ललित मेहरा, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात विभाग, राजस्थान सरकार ने कट्स द्वारा 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस'के उपलक्ष्य में 18 मार्च, 2013 को जयपुर में आयोजित सेमीनार में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने साथियों, आस-पड़ोस के लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक बनाएं। इस बात पर भी गहन विचार करना होगा कि उपभोक्ताओं को न्याय समय पर मिले। यह एक गंभीर विचारणीय विषय है, क्योंकि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं कहलाता।

कार्यशाला में मिस अन्ना रूथ, कार्यक्रम निदेशक, जीआईजेड, नई दिल्ली; अमृत लाल साहा, अध्यक्ष, कन्ज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउन्सिल; डॉ. पूनम पाण्डे, तकनीकी एक्सपर्ट, जीआईजेड नई दिल्ली; मिस एस. सरोजा, सीएसजी, चैन्नई; डॉ. केया घोष, कट्स कोलकाता सेन्टर; जॉर्ज चेरियन, निदेशक कट्स, जयपुर तथा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोड़ा ने मुख्य वक्ता के रूप में भागीदारों को सम्बोधित किया।

इस अवसर पर श्री मेहरा ने ग्रेनिका परियोजना के तहत राज्य में जिला स्तरीय सहयोगी संस्थाओं को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों की स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग और मंत्रालय के अधिकारी व मीडिया प्रतिनिधियों सहित 75 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! चुनावी साल के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में जमकर लोक-लुभावनी घोषणाएं की हैं।

वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को कुछ न कुछ देकर लुभाने की कोशिश बजट में साफ झलकती है। इससे बजट निष्क्रिय लगने लगा है। बजट के जानकार लोगों का मानना है कि चुनावी साल में इन सभी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाना काफी मुश्किल काम है।

बजट में बुनियादी जरूरतों जैसे चिकित्सा, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क आदि से सम्बन्धित प्रावधानों के साथ-साथ गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, छात्रों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों को राहत देने की बात भी की गई है। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार पेट्रोल-डीजल पर से वैट कम कर राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

जोधपुर को सोलर सिटी बनाने, 16 मेडिकल कॉलेज खोलने, कृषि विश्व विद्यालय व तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना जैसी घोषणाएं स्वागतयोग्य कदम हैं। लेकिन, देखना यह है कि इनमें से सरकार किन-किन घोषणाओं को चुनाव से पूर्व धरातल पर उतारने में सफल हो पाती है।

जो भी हो.. सरकारी बजट 'आंकडों का जाल' होता है और आम ग्रामीण सही रूप में उसे समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर नजर रख सकें और लाभान्वित हो सकें।

सरकारी सेवा में देरी तो 50 हजार रुपए तक होगा जुर्माना

सरकारी सेवा में देरी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर अब 50 हजार तक जुर्माना लग सकता है। केन्द्रीय कैबिनेट ने इस संबंध में सिटीजन चार्टर विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें पासपोर्ट, पेंशन और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने का प्रावधान है। विधेयक को अभी संसद में पारित कराया जाना बाकी है।

प्रस्तावित कानून में यह है प्रावधान

- *सरकारी विभागों को सिटीजन चार्टर प्रकाशित करना होगा। उसमें यह बताना होगा सेवा कितने दिन में मुहैया कराई जाएगी।*
- *समय सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराएं जाने पर शिकायतों के निपटारे के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था भी होगी।*
- *केन्द्रीय विधेयक में राज्यों की सेवाएं भी शामिल होंगी। नगर निगम व राज्य सरकार की सेवाओं पर भी केन्द्रीय कानून लागू होगा।*
- *केन्द्र व राज्य स्तर पर लोक शिकायत निवारण आयोग बनाने का प्रस्ताव है।*

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भारी पड़ा पास को पूरक घोषित करना

पीपाड़ सिटी निवासी छात्र महावीर बोहरा ने जिला उपभोक्ता मंच में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के खिलाफ परिवाद दायर किया। उसने मंच को बताया कि नियमित छात्र के रूप में वर्ष 2012 में उसने 12वीं की परीक्षा दी थी। बोर्ड ने उसे अर्थशास्त्र में 5 अंक देकर पूरक परीक्षा के योग्य बताते हुए परिणाम घोषित कर दिया। उसने अपनी उत्तर पुस्तिका की दुबारा जांच कराई। क्योंकि उसके अन्य विषयों में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए थे और इस विषय में इतने कम अंक आने की उसने सपने में भी नहीं सोची थी।

उसे आश्चर्य तो तब हुआ जब बोर्ड ने दुबारा जांच करके बताया कि परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं है। इसपर उसने सूचना के अधिकार के तहत बोर्ड से उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त की तब जाकर उसे पता चला कि अर्थशास्त्र में उसे 5 की जगह 50 अंक मिले हैं।

मामले की सुनवाई पर बोर्ड की ओर से यह दलील दी गई कि वह मात्र परीक्षाएं आयोजित कराता है, इसलिए सेवा प्रदाता की श्रेणी में नहीं आता। मंच ने बोर्ड के इस कथन को गैर जिम्मेदाराना कृत्य माना और छात्र के भविष्य से खिलवाड़ करने का दोषी करार दिया। मंच ने बोर्ड को आदेश दिया कि वह छात्र महावीर बोहरा को पूरक परीक्षा शुल्क सहित 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में व दो हजार रुपए मुकदमा खर्च अदा करे।

आमजन की रसोई पर राहत के छींटें

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों पर वर्तमान में आमजन को 8.10 रु.प्रति किलो मिलने वाला 10 किलो आटा अब 5 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा। इन दुकानों पर तेल, चाय, बिस्किट, मसाले, साबुन आदि भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाने की घोषणा बजट में की गई है। बाजार में मिलने वाले साबुत मसालों को भी वैट मुक्त किया गया है।

केन्द्र सरकार की घोषणा के अनुसार अब हर परिवार को एक साल में सब्सिडी वाले 9 रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। इसे मंहगाई के बोझ के नीचे दबे आम आदमी की रसोई पर राहत बताया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार का खाद्य सुरक्षा बिल अभी आमजन के लिए एक सपना ही है। इस पर अभी फैसला होना बाकी है।

बीपीएल-एपीएल को दी सहूलियतें

प्रदेश के बजट में बीपीएल परिवारों के लिए सहूलियतों का पिटारा खोला गया है। उन्हें अब दो रुपए किलो के बजाय एक रुपए किलो गेहूं व 10 रुपए किलो चीनी मिलेगी।

महिलाओं को दो-दो साड़ियां और पुरुषों को एक-एक कम्बल मुफ्त दिया जाएगा। हर परिवार को दो सीएफएल बल्ब और बीपीएल आवास योजना में अब 70 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।

जिन परिवारों की सालाना आय एक लाख रुपए तक है और परिवार में कोई व्यक्ति हृदय, कैंसर या किडनी की बीमारी से ग्रसित है, तो उसे इलाज की सुविधा व एक लाख रुपए तक की सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी।

नहीं मिला रोजगार

प्रदेश में पिछले तीन सालों से गरीबी कम करने वाली मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2010-2011 में जहां करीब 3027 लाख लोगों को रोजगार मिला था, वह सिमट कर केवल 1541 लाख लोगों तक रह गया है।

एक सर्वे के मुताबिक महिला सुरक्षा में प्रदेश 26वें स्थान पर है। ऐसी और भी कई समस्याएं गिनाई जा सकती हैं। अखबारों में छपी ये खबरें हर नागरिक को उद्वेलित करती हैं।

- राम चरण माली, सूरजपोल, जयपुर

किसानों के लिए खोला पिटारा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में कृषि विश्वविद्यालय खोलने तथा वर्ष 2013-14 में किसानों को 15 हजार करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरित किए जाने की घोषणा की है। ब्याजमुक्त ऋण की राशि को बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए कर दिया गया है।

बाजार भावों की जानकारी के लिए एग्री मार्केट इंटेलिजेंस एवं बिजनेस प्रमोशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ दिए जाने वाले बोनस की राशि को 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए किया गया है।

महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता

केन्द्रीय बजट में 97 हजार 134 करोड़ रुपए का प्रावधान जेंडर बजट के रूप में किया गया है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए का 'निर्भया फंड' बनाने जैसे कई वादे भी किए गए हैं।

प्रदेश के बजट में मुख्यमंत्री ने राजस्थान सहकारी व वित्त विकास निगम की स्थापना करने की घोषणा की है। निगम का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की साख सम्बन्धी जरूरतों की पूर्ति करना होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए टोल फ्री हैल्प लाइन शुरू की जाएगी।

लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए शुभलक्ष्मी योजना लागू की जाएगी। जिसमें बालिका के जन्म पर एक हजार रुपए, एक वर्ष की होने पर एक हजार रुपए तथा पांच साल की होने पर दो हजार रुपए दिए जाएंगे।

अनाज गोदामों के लिए मिलेगा पैसा

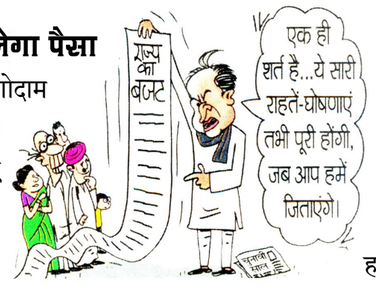

पंचायतों में अनाज भंडारण के गोदाम बनाने के लिए नाबार्ड पैसा देगा। केन्द्रीय बजट में नाबार्ड के जरिए देश भर के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में 8 लाख टन भंडारण क्षमता के गोदाम बनाने के लिए नाबार्ड के सहयोग से योजना बनाई गई है। इसमें 125 करोड़ की योजना पर काम शुरु किया जा चुका है। केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा से राजस्थान को गोदाम बनाने के लिए अतिरिक्त पैसा मिलेगा।

पढ़ोगे- लिखोगे तो मिलेगा ईनाम

बजट प्रस्ताव अनुसार राज्य में 15 राजकीय महाविद्यालय, प्रदेश की हर पंचायत में माध्यमिक स्कूल एवं 1000 नए प्राथमिक स्कूल खुलने से शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अभी भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से निजात नहीं मिल पाई है।

सरकार कक्षा आठवीं में दूसरे से ग्यारवां स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 6 हजार रुपए की कीमत के टेबलेट पीसी दिए जाएंगे।

बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा का न्योता

बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा का न्योता दिया है। उन्हें रेलों के माध्यम से देश के तीर्थ स्थानों की मुफ्त यात्रा कराने के मकसद से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई है।

नए साल में प्रदेश के 25 हजार लोगों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रदेश से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इससे पहले यह राशि बीस हजार रुपए थी। बजट में राजस्थान वृद्धाश्रम योजना लागू करने की घोषणा भी की गई है। प्रदेश में मिल रही वृद्धावस्था, विधवा व विशेष योग्यजन पेंशन जरूरतमंदों को अब आजीवन मिलेगी।

ग्रामीण विकास को अहमियत

प्रदेश के बजट में 3616 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान ग्रामीण विकास के लिए किया गया है। दस हजार से अधिक जनसंख्या वाले 81 गांवों में विकास के लिए एक-एक करोड़ रुपए अलग से खर्च किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी खोली जाएगी।

दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना लागू की जाएगी। पशुधन निःशुल्क दवा योजना में दवाओं की संख्या 87 से बढ़ाकर 110 की है।

तीन हजार गांव-ढाणियों को शुद्ध पेयजल लाइन से जोड़ा जाएगा तथा सड़क और परिवहन सुधार के लिए एक विशेष कोष बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में मनरेगा योजना में 125 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। लेकिन लिखित भाषण में रोजगार दिवस 150 दिए गए हैं। इससे अभी विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने 100 दिन का रोजगार पूरा करने पर 2100 रुपए का ईनाम देने की भी घोषणा की है। इससे मनरेगा श्रमिकों को लाभ मिल सकेगा।

जन स्वास्थ्य के पलड़े पर खास नजर

बजट में सेहत को खास तबज्जो दी गई है। प्रदेश के 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने, मुफ्त दवा योजना के तहत मिल रही 400 दवाओं की संख्या को बढ़ाकर 600 करने और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच योजना को तीन चरणों में लागू किए जाने की घोषणा की गई है।

इस योजना की शुरुआत 7 अप्रेल 2013 से शुरू की जा रही है। पहले चरण में राज्य के 86 अस्पतालों में, जुलाई 2013 से 428 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी 1649 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इस योजना को लागू किया जाएगा।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485